संख्या– / / XVIII(II) / 2021–03(38) / 2021

प्रेषक,

डा0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 30 दिसम्बर, 2021

विषयः– जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना (119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 है0 राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–246 / सात–03 / 2021–22, दिनांक 09 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सीमान्त क्षेत्र की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए (119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ जनपद, पिथौरागढ़, तहसील धारचूला, ग्राम गुंजी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी, श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या–39 के खेत नं0 2257 मध्ये रकबा 3.430 है0, 2260 मध्ये रकबा 0.550 है0, 2266 मध्ये रकबा 1.500 है0, 2282 मध्ये रकबा 1.870 है0, 2288 मध्ये रकबा 2.000 है0, 2289 मध्ये रकबा 2.000 है0 इस प्रकार कुल 06 खेतों की 11.350 है0 राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीमान्त क्षेत्र की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए (119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ जनपद, पिथौरागढ़, तहसील धारचूला, ग्राम गुंजी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी, श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या–39 के खेत नं0 2257 मध्ये रकबा 3.430 है0, 2260 मध्ये रकबा 0.550 है0, 2266 मध्ये रकबा 1.500 है0, 2282 मध्ये रकबा 1.870 है0, 2288 मध्ये रकबा 2.000 है0, 2289 मध्ये रकबा 2.000 है0 इस प्रकार कुल 06 खेतों की 11.350 है0 राज्य भूमि को शासनादेश सं0–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496 / XVII(II) / 2020–08(63) / 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का नजराना रू0 1,19,17,500 / –(एक करोड़ उन्नीस लाख सत्रह हजार पांच सौ रू0 मात्र) तथा मालगुजारी रू0 97 / – (सत्तानब्बे रू0 मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,19,17,597.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख सत्तरह हजार पांच सौ सत्तानब्बे रू0 मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

....2

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

6– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

10– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

....3

संख्या– 1917 /XVIII(II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– लेफ्टिनेंट कर्नल, 119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप, द्वारा 56 ए0पी0ओ0।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।